EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By: - Aarav Anand
Date: 06 Dec 2025
Source:- जनसत्ता

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा

रुपया अपने को खुद ही संभाल लेगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

लगातार गिर रहे रुपए को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपए के लिए कोई लक्षित स्तर या दायरा नहीं रखता है और घरेलू मुद्रा को खुद ही अपना सही स्तर खोजने की अनुमति देता है।

मल्होत्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रुपया इसी हफ्ते अमेरिकी डालर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर अपने सबसे निचले भाव पर पहुंच गया। गुरुवार को इसने 90.43 रुपए प्रति डालर का रिकार्ड निचला स्तर छुआ था।

मल्होत्रा ने कहा कि हम रुपए के लिए मूल्य का कोई स्तर या दायरा नहीं रखते हैं। हम बाजारों को ही कीमतें तय करने देते हैं। लंबी अवधि में बाजार काफी प्रभावी होते हैं। यह एक बहुत बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि बाजार में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और आरबीआइ का प्रयास हमेशा असामान्य या अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करना होता है। आरबीआइ ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में इस महीने पांच अरब अमेरिकी डालर की तीन-वर्षीय डालर/रुपया खरीद-बिक्री अदला-बदली करने का फैसला किया है। इस कदम पर मल्होत्रा ने कहा कि यह रुपए की गिरावट को रोकने का प्रयास नहीं है बल्कि यह एक नकदी उपाय है।

आरबीआइ डालर-रुपया खरीद-बिक्री अदला-बदली के तहत बैंकों से डालर खरीदता है और बाद में उन्हें वापस बेचने के लिए सहमत होता है। इसका मकसद रुपए में तरलता बढ़ाना, विनिमय दरों का प्रबंधन करना और बैंकों को विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में मदद करना है। मल्होत्रा ने कहा कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं और चालू खाता भी संतुलित है।

आरबीआइ ने रेपो दर 0.25 फीसद घटाई, सस्ते होंगे आवास और वाहन ऋण पेज 10

मानव-वन्यजीव संघर्ष

उत्तराखंड में 25 वर्षों में

वन्यजीवों के हमलों में 900 से अधिक मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

उत्तराखंड में 25 वर्षों में बाघों, तेंदुओं, भालुओं और अन्य जानवरों के हमलों में 900 से अधिक लोगों की जान गई है और यह स्थिति पर्वतीय राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के खतरनाक स्तर को उजागर करती है। वहीं, संसद के दोनों सदनों में वन्य जीवों से लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की मांग उठाई गई।

नवीनतम घटना गुरुवार को हुई जब पौड़ी जिले के गजाल्ड गांव में तेंदुए के हमले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह वह जिला है, जहां जानवरों के हमले के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं और जिसके बाद प्रशासन को कई कदम उठाने पड़े। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 वर्षों में उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण 900 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें तेंदुए के हमले में 548, हाथी के हमले में 230, बाघ के हमले में 106 और भालू के हमले में 70 लोग मारे गए हैं। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान राज्य में सर्पदंश से 260 लोगों की जान गई। इस बीच, तेंदुओं के हमलों में 2,127, भालू के हमलों में 2,013, हाथियों के हमलों में 234 और सांप के काटने से 1,056 लोग घायल हुए। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य के लगभग हर हिस्से में तेंदुए के हमले पूरे वर्ष देखे जाते हैं, जबकि भालू के हमले

बाकी पेज 8 पर

उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार 25 वर्षों में उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में तेंदुए के हमले में 548, हाथी के हमले में 230, बाघ के हमले में 106 और भालू के हमले में 70 लोग मारे गए हैं।

तेंदुओं के हमलों में 2,127, भालू के हमलों में 2,013, हाथियों के हमलों में 234 और सांप के काटने से 1,056 लोग घायल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को न्यायिक प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के इस्तेमाल को लेकर जज पूरी तरह सतर्क हैं और ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि इसके प्रयोग को अनियंत्रित तरीके से होने दिया जा रहा हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कथित दुरुपयोग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका किसी भी सूरत में एआइ या मशीन लर्निंग को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालतों में जेनरेटिव एआइ के कथित अनियमित उपयोग को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हमारे द्वारा अनियंत्रित उपयोग का कोई सवाल ही नहीं है। मैं और मेरे सभी साथी जज पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम एआइ का उपयोग बेहद सावधानी के साथ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एआइ या मशीन लर्निंग न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर हावी हो।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अनुपम लाल दास ने दलील दी कि कुछ मामलों में वकीलों द्वारा एआइ से तैयार किए गए फर्जी न्यायिक नजीर (फेक प्रीसिडेंट्स) अदालतों में पेश किए गए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे नकली प्रीसिडेंट्स संभवतः इसलिए सामने आए हैं, क्योंकि कुछ वकीलों ने खुद ऐसे काल्पनिक फैसलों का हवाला दिया होगा। उन्होंने साफ किया कि वकीलों को भी एआइ के दुरुपयोग को लेकर सतर्क रहना होगा और झूठे या गढ़े हुए दस्तावेजों पर निर्भर रहना उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों के खिलाफ है।

भाषाओं पर मंडराता विलुप्ति का खतरा

एक तरफ वैज्ञानिक तकनीक के जरिए पशु-पक्षियों की भाषाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मानव समाज अपनी पारंपरिक भाषाओं को लेकर असंवेदनशील होता जा रहा है। यूनेस्को की रपट के अनुसार, इस समय दुनिया की 576 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं।

अतुल कनक

वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस का ऐसा उपकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानवरों की भाषाओं को समझ सके। यदि ऐसा संभव हुआ, तो यह मानव इतिहास में एक नई क्रांति होगी, क्योंकि पशु-पक्षी प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और कुछ तरंगों से इस तरह स्पंदित होते हैं कि आने वाली घटनाओं की अनुभूति उन्हें पहले ही हो जाती है। भारतीय वांग्मय में ऐसे कुछ पात्रों का उल्लेख है, जो पशु-पक्षी की बात सुनते थे। यदि एआइ इस गुण को जनसामान्य को उपलब्ध करा पाता है, तो यह तकनीक निश्चित रूप से जीवन को एक नए सांचे में ढालने में मदद करेगी। मगर जो मनुष्य समाज पशु-पक्षियों की भाषाओं को समझने का प्रयास कर रहा है, वही अपनी पारंपरिक भाषाओं को लेकर असंवेदनशील होता जा रहा है। इसका अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ की एजंसी 'यूनेस्को' के उस मानचित्र से लगाया जा सकता है, जो उसने दुनिया की संकटग्रस्त भाषाओं के बारे में जारी किया है। 'एटलस आफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर' के अनुसार, इस समय दुनिया की 576 भाषाओं पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, यानी वे लुप्त होती प्रतीत हो रही हैं। इसके अलावा, हजारों अन्य भाषाएं भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं।

भाषाएं केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे किसी समाज विशेष की हजारों साल की परंपराओं और उसके अनुभवों की वाहक भी होती हैं। इस बात का अनुमान राजस्थानी भाषा के विभिन्न रूपों से लगाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान का बड़ा भू-भाग मरुस्थल है। इस क्षेत्र में बरसात का अपना महत्त्व होता है। राजस्थानी भाषा में विक्रमी कैलेंडर के हर महीने में होने वाली बारिश के लिए एक अलग नाम है। चैत्र माह में होने वाली बारिश को चड़पड़ाट, बैसाख की बारिश को हलोतियो और जेठ माह की बारिश को झपटो कहा जाता है। इसी तरह से अन्य माह में होने वाली बारिश के लिए अलग-अलग संबोधन हैं। उन्हें क्रमशः सरवांत (आषाढ़), लेर (सावन), झड़ी (भाद्रपद), मोती (आश्विन), कटक (कार्तिक), फांसरड़ी (मार्गशीर्ष), पावठ (पोष), मावठ (माघ) और फटकार (फागुन की बारिश) कहा जाता है। ठीक इसी तरह राजस्थानी भाषा में ऊंट के 270 से अधिक पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और सहेजना आवश्यक है।

भाषाएं समाज की सांस्कृतिक पहचान भी होती हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में लार्ड मैकाले की ओर से सुझाई गई अंग्रेजी आधारित शिक्षा पद्धति लागू करने का एक उद्देश्य यह भर था कि भारतीयों को उनके सांस्कृतिक गौरव से वंचित किया जाए। अंग्रेज अधिकारियों के परस्पर पत्र व्यवहार से इस बात का खुलासा आजादी के बाद हुआ। किसी समाज की अभिव्यक्ति को कमजोर करने के लिए औपनिवेशिक ताकतें इस तरह के हथकंडे अपनाया करती थीं।

पिछली सदी में औसतन हर तीन महीने में एक देशज भाषा लुप्त हुई है। भाषाविदों का मानना है कि इसी तरह की स्थितियां रहीं, तो दुनिया में इस समय काम में आने वाली भाषाओं में से आधी इस सदी के अंत तक यानी अगले

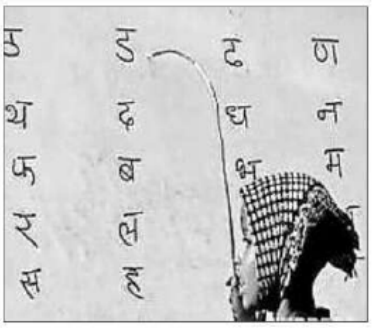

पचहत्तर वर्षों में लुप्त हो जाएंगी। यह आशंका इसलिए भी डराती है, क्योंकि वर्ष 1950 से 2010 के बीच दुनिया की 230 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं और यूनेस्को के अनुसार, हर चौदह दिन में एक भाषा समाप्त हो रही है। कुछ भाषाएं तो मानव समाज की लापरवाही के कारण मृत अवस्था में पहुंच गई हैं।

> **भा**षाओं के प्रति कुछ ताकतवर लोगों के अपने दुराग्रह भी हैं। कुछ समय पहले चीन में एक भाषाविद को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा उइगर को बचाने के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे। ऐसे दुराग्रह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। कहीं कोई भाषा बोल पाने में अक्षम ऐसे लोगों को सताया जाता है, जो उस भाषाभाषी समूह का सदस्य ही नहीं होते, तो कहीं किसी भाषा विशेष के संरक्षण के नाम पर दूसरी भाषा का विरोध किया जाता है। जबकि जो भाषाएं संकट में हैं, उन्हें बचाए जाने के सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।

अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा बोली जाती थी-'बो'। उसे बोलने वाले धीरे-धीरे कम होते चले गए। अंत में बोआ नाम की एक 85 वर्षीय महिला बची जो इस भाषा को बोल एवं समझ सकती थीं। संस्थागत स्तर पर उनसे संवाद करके इस भाषा के संग्रहण का काम होता, तो कदाचित इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी 2010 को बोआ का निधन हुआ और उनके साथ ही 'बो' ने भी दम तोड़ दिया। ऐसा ही 'खोरा' भाषा के साथ भी हुआ। प्री कोलंबियाई मैक्सिकन भाषा 'अयापानेको' के संदर्भ में तो और भी रोचक बात हुई। इस भाषा को बोलने एवं समझने वाले दो ही व्यक्ति बचे थे। भाषाविदों ने इन दोनों के परस्पर संवाद से इस भाषा को सहेजने का प्रयास किया, लेकिन इनके बीच आपसी विवाद पैदा हो गए। इसलिए दोनों ने वर्षों तक एक-दूसरे से संवाद ही नहीं किया। इन वैयक्तिक पूर्वाग्रहों ने इस भाषा को संकट में धकेल दिया। रोजगार के सिलसिले में अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति या विवशता ने भी लोगों को अपनी भाषाओं से दूर किया है। पराये शहर में वे अपने अस्तित्व और आर्थिक उन्नयन के लिए जूझते या भाषा के प्रति अपनी संवेदना को बचाते?

शिकागो विश्वविद्यालय में भाषाविद रहे सालिकोको मुफवेने की मातृभाषा कियानसी थी। यह भाषा कांगो गणराज्य में एक छोटे जातीय समूह द्वारा बोली जाती है। अपने पैतृक स्थान से दूर रहने वाले सालिकोको का कहना है कि उन्हें चार दशक के अपने प्रवास में कियानसी बोलने वाले दो ही लोग मिले। ऐसे में अपनी मातृभाषा बोलने का उनका अभ्यास जाता रहा। अक्सर संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे अपने दादा-दादी या अन्य बुजुर्गों से मातृभाषा में संवाद करते हैं, लेकिन एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने अधिकांश बच्चों को अपनी पारंपरिक भाषाओं से दूर कर दिया। करियर की होड़ तो उन्हें कुछ खास भाषाओं की ओर उन्मुख करती है। भारत में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की नीति बनाई है। यह समय बताएगा कि यह नीति समाज की भाषाई विविधता को बचाए रखने में कितनी भूमिका अदा करती है।

वहीं, भाषाओं के प्रति कुछ ताकतवर लोगों के अपने दुराग्रह भी हैं। कुछ समय पहले चीन में एक भाषाविद को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वे अपनी मातृभाषा उइगर को बचाने के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे। ऐसे दुराग्रह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। कहीं कोई भाषा बोल पाने में अक्षम ऐसे लोगों को सताया जाता है, जो उस भाषाभाषी समूह का सदस्य ही नहीं होते, तो कहीं किसी भाषा विशेष के संरक्षण के नाम पर दूसरी भाषा का विरोध किया जाता है। जबकि जो भाषाएं संकट में हैं, उन्हें बचाए जाने के सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। ईमानदार और जिम्मेदार कोशिशें हों, तो संकट में पड़ी हुई भाषाओं को बचाया जा सकता है। भूमिज भाषा का उदाहरण लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओड़ीशा के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली यह देशज भाषा यूनेस्को द्वारा अतिसंकट में घोषित भारत की 197 भाषाओं में एक थी। वर्ष 2018 में इस समाज के कुछ जागरूक युवाओं ने अपनी भाषा को बचाने के लिए स्कूल खोले और आनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरू किए। उनकी पहल रंग लाई, पचास हजार से अधिक युवाओं ने इस पहल के बाद भूमिज भाषा को सीखा है। दरअसल, भाषाएं संकट में आती ही इसलिए हैं, क्योंकि नई पीढ़ी उनके उपयोग के प्रति उदासीन हो जाती है। संपूर्ण समाज को भाषाओं के प्रति संवेदनशील होना होगा, क्योंकि भाषाएं मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का आभूषण हैं।

वक्फ पंजीकरण की समयसीमा नहीं बढ़ेगी : किरेन रिजीजू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की संभावना से शुक्रवार को इनकार किया और कहा कि उन 'मुत्तवलियों' (वक्फ का देखभाल करने वाले) को तीन महीने तक जुर्माने और किसी कठोर सजा से राहत दी जाएगी, जो पंजीकरण करने का प्रयास करते हुए किसी वजह से सफल नहीं हो सके।

उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार सुबह तक 1.51 लाख संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका था। मंत्री का यह भी कहना था कि जो लोग पंजीकरण नहीं कर पाए हैं वो वक्फ न्यायाधिकरण का रुख कर सकते हैं।

केंद्र ने सभी वक्फ संपत्तियों की 'जियो-टैगिंग' के बाद एक डिजिटल सूची बनाने के लिए बीते छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम केंद्रीय पोर्टल शुरू किया था। 'उम्मीद' पोर्टल के प्रावधान के अनुसार, देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है। पंजीकरण के लिए छह महीने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है।

रिजीजू ने कहा कि वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए संबंधित पक्षों को छह महीने की अवधि दी गई थी। आज आखिरी दिन है और अब भी लाखों संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सका है। कई सांसदों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पोर्टल की मियाद बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अब तक उम्मीद पोर्टल पर 1.51 लाख वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है। मंत्री ने कहा कि मैं उन भी मुतवल्लियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीनों तक कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे या कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने पंजीकरण की कोशिश की, किसी कारणवश पंजीकरण नहीं हो सका।

विमान सेवाओं में व्यवधान से हवाई अड्डों पर चौथे दिन भी अफरा-तफरी **परेशानी** पायलटों के उड़ान समय के नए नियम बनाने में विफल होने से बढ़ी समस्या

इंडिगो का संकट गहराया, सरकार ने दिए जांच के आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के राष्ट्रीय राजधानी से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों सहित करीब 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करने से देश भर में हजारों यात्री कई घंटों तक फंसे रहे और हवाई यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी पटरी से उतरी नजर आई। इंडिगो के पायलटों के उड़ान-समय के लिए नए नियमों की योजना बनाने में विफल रहने के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ।

लोगों का गुस्सा बढ़ने और विपक्षी दलों के सरकार को घेरने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो के पायलटों के लिए रात्रि ड्यूटी के कड़े नियमों से अस्थायी छूट दे दी। यह मामला इतना बढ़ गया कि संसद तक भी पहुंच गया। हवाई अड्डों पर तीन दिन से मची अफरा-तफरी के मद्देनजर नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बयान में कहा, ' हमें उम्मीद है कि अगले तीन दिन में सेवाएं पूरी तरह बहाल हो जाएंगी। विभिन्न परिचालनात्मक कदमों की शुरुआत के साथ कल (शनिवार) तक सेवाएं सामान्य हो जाने की उम्मीद है।' उन्होंने कहा, ' नए उड़ान शुल्क मानदंडों को स्थगित रखा जा रहा है और परिचालन को सामान्य बनाने के लिए अन्य परिचालनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।' गंभीर परिचालन संकट से गुजर रही इंडिगो की उड़ानों के समय पर संचालन की दर गुरुवार को घटकर 8.5 प्रतिशत पर आ गई। इंडिगो सामान्यतः प्रतिदिन करीब 2,300 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। अब वह मुख्य रूप से चालक दल की कमी से उत्पन्न हुए व्यवधानों के कारण बड़ी संख्या में अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। इंडिगो को समय पर सेवाएं देने के लिए पहचाना जाता रहा है।

जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारणों की समीक्षा और आकलन के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। शुक्रवार को जारी एक आदेश के मुताबिक, समिति के सदस्यों में संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्मने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक और उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि समिति 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ताकि जरूरी नियामक प्रवर्तन कार्रवाई की जा सके। आदेश के अनुसार, प्रथम दृष्टि में स्थिति आंतरिक निरीक्षण, परिचालन तैयारियों और अनुपालन योजना में कमियों का संकेत देती है, जिसके लिए स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

भारत-रूस व्यापार मंच से संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

वर्ष 2030 तक 100 अरब डालर व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि भारत और रूस के बीच 100 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए मोदी ने रूसी कंपनियों को न्योता देते हुए कहा, 'आइए और भारत में बनाइए... भारत के साथ साझेदारी कीजिए।'

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले साल राष्ट्रपति पुतिन और उन्होंने 2030 तक 100 अरब डालर के आपसी व्यापार का लक्ष्य तय किया था। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन के साथ आगे बातचीत के बाद तथा हमारी साझेदारी में जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य तय समय से काफी पहले हासिल कर लेंगे। हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।' मोदी ने कहा कि कारोबार के लिए सरल और भरोसेमंद व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कारोबार हो या कूटनीति, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास होती है।

मोदी ने बताया कि भारत सस्ते और कुशल इलेक्ट्रिक वाहनों, दोपहिया वाहनों तथा सीएनजी परिवहन समाधानों में अग्रणी है, जबकि रूस उन्नत सामग्रियों का बड़ा उत्पादक है। ईवी विनिर्माण, आटोमोटिव कलपुर्जा और गतिशीलता तकनीकों में साझेदारी करके दोनों देश न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक दक्षिण के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी कंपनियां भारत से विभिन्न तरह के सामान और सेवाओं की खरीद बढ़ाने को तैयार हैं।

पुतिन को भगवद गीता का एक रूसी संस्करण भेंट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार स्वरूप असम की स्वादिष्ट काली चाय, कश्मीरी केसर, हस्तनिर्मित घोड़े की चांदी की प्रतिकृति, एक सजावटी टी सेट, आगरा से हस्तनिर्मित संगमरमर का शतरंज सेट और भगवद गीता का एक रूसी संस्करण भेंट किया। वहीं राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण शिखर वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के दौरान 'गार्ड आफ आनर' दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रूसी राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

भारत-ईएईयू व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर के पक्ष में पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं यूरेशियाई आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच तरजीही व्यापार समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर होने से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह में बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी। भारत और ईएईयू ने पिछले सप्ताह इस मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर पहले दौर की बातचीत की थी। ईएईयू के पांच सदस्य देशों- रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एवं किर्गिजस्तान के साथ भारत ने 20 अगस्त को समझौते के लिए नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिया था। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पुतिन ने यहां भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के प्रवाह के लिए बाधाएं कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच प्राथमिक व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर से एक मजबूत प्रोत्साहन दिया जा सकता है।'

भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के नवीनतम प्रयासों का शुक्रवार को पुरजोर समर्थन किया और राष्ट्रपति पुतिन को यह संदेश दिया कि भारत इस संघर्ष का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सभी शांति प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।

यूक्रेन मुद्दा दोनों नेताओं के वार्षिक शिखर वार्ता में केंद्रीय रूप से उभरा है। इस शिखर वार्ता का उद्देश्य लगभग आठ दशक से जारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाना है, जो जटिल भू-राजनीतिक माहौल और तनावों के बावजूद स्थिर बनी रही है। मोदी ने शिखर वार्ता के दौरान अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को लेकर तटस्थ नहीं है, बल्कि इसे करने के लिए शांति का पक्षधर है।

उन्होंने कहा, 'यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के बाद से हम चर्चा करते रहे हैं। एक करीबी मित्र के रूप में, आप हमें स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित करते आए हैं। मुझे लगता है कि विश्वास एक बड़ी ताकत है। हम सभी को शांति का मार्ग तलाशना चाहिए। मैं नवीनतम प्रयासों से अवगत हूं और मुझे विश्वास है कि दुनिया शांति की ओर रुख करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का एक पक्ष है और वह है शांति। हम सभी शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं।

भारत और रूस ने पंचवर्षीय आर्थिक मसविदे पर सहमति जताई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

भारत और रूस ने अमेरिका द्वारा दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमति जताई। दोनों देशों ने 2030 के आर्थिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के अलावा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत-रूस साझेदारी का एक मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रही है और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मोदी ने कहा, 'महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में हमारा सहयोग दुनिया भर में सुरक्षित और विविध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, उच्च तकनीक विनिर्माण और नए युग के उद्योगों में हमारी साझेदारियों को ठोस आधार मिलेगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाना प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, 'हम आइएनएसटीसी, उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी 'मल्टी-मोड' परिवहन परियोजना है। पुतिन ने संकेत दिया कि रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाएगा तथा दोनों पक्ष छोटे एवं 'माड्यूलर' परमाणु रिएक्टर तथा 'फ्लोटिंग' परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग के लिए उत्सुक हैं।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया | **सूचना** | उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 157 स्टेशन, 22 पर विकास कार्य पूर्ण

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1337 स्टेशन चयनित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1337 स्टेशन का विकास करेगी। इसमें सर्वाधिक 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। 22 पर विकास कार्य पूर्ण भी हो चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि 1337 रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है।

योजना के तहत स्टेशन का विकास आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में चयनित स्टेशनों में अयोध्या धाम, गोमती नगर, गोंडा, बरेली सिटी, बलरामपुर, बिजनौर, इज्जतनगर, सहारनपुर, फतेहपुर, पंकी धाम समेत अनेक स्टेशन शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि यात्रियों की मांग को ध्यान

मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान भारतीय रेल पर कुल 2,617 किलोमीटर लंबाई की 21 मीटर गेज से ब्राड गेज रूपांतरण परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 19,485 करोड़ रुपए है।

में रखते हुए 12 दिसंबर से छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस का पडरौना में ठहराव शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर-वाल्मिकीनगर दोहरीकरण (96 किमी) और छितौनी-तमकुही रोड नई रेल लाइन (63 किमी) सहित दूसरी बड़ी परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान भारतीय रेल पर कुल 2,617 किलोमीटर लंबाई की 21 मीटर गेज से ब्राड गेज रूपांतरण परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 19,485 करोड़ है। इसके अलावा, क्षेत्रीय संपर्क और जिला मुख्यालयों को जोड़ने के उद्देश्य से 755 किलोमीटर लंबाई की 18 अतिरिक्त ब्राड गेज परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इनकी मदद से यात्री आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर शुरू हुई कवच 4.0 की सुविधा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

रेल दुर्घटनाओं की आशंका को दूर करने के लिए विकसित स्वदेशी तकनीक कवच 4.0 को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर पलवल-मथुरा-नागदा अनुभाग (633 मार्ग किमी) और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर हावड़ा-बर्धमान अनुभाग (105 किमी) पर चालू किया गया। साथ ही 15512 मार्ग किमी पर ट्रैक साइड कवच का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रेलवे के सभी स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम विकर्ण, उच्च घनत्व नेटवर्क और चिन्हित खंड शामिल हैं।

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि जुलाई 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाए गए इस तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 मार्ग किमी पर कवच संस्करण 3.2 की तैनाती और प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें और सुधार किए गए।

राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अहमदाबाद 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा : अमित शाह

अहमदाबाद, 5 दिसंबर (भाषा)।

संबोधन

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि अहमदाबाद शहर को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार मिलेगा।

हाल में अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार मिला है। शाह ने यहां 'संसद खेल महोत्सव' के समापन समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा,' आपने हाल में राष्ट्रमंडल खेलों की बोली जीती है। लेकिन अहमदाबाद के लोगों तैयार रहो क्योंकि यह शहर 2036 में ओलंपिक का भी स्वागत करने जा रहा है।' शुक्रवार से तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर आए शाह ने कहा कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने से पहले शहर 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों सहित लगभग एक दर्जन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। यह महोत्सव अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में नवनिर्मित वीर सावरकर खेल परिसर में आयोजित किया गया था जो शाह के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है।

जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

भारतीय टीम ने बेल्जियम को 4-3 से हराया, सात दिसंबर को जर्मनी से होगा सामना

चेन्नई, 5 दिसंबर (भाषा)।

निर्धारित समय में आखिरी मिनट में गोल गंवाने के बाद भारतीय टीम ने बेल्जियम को शुक्रवार को यहां शूटआउट में गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के शानदार प्रदर्शन के दम पर 4-3 से हराकर जूनियर हाकी विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

भारत का सामना अब सात दिसंबर को जर्मनी से होगा जबकि स्पेन की भिड़ंत अर्जेंटीना से होगी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था। भारतीय टीम को आखिरी सीटी बजने से एक मिनट पहले कोताही बरतने का खामियाजा भुगतना पड़ा और रोजे नाथन के गोल की मदद से बेल्जियम ने मैच को शूटआउट तक खींच दिया। शूटआउट में भारत के लिए शारदानंद तिवारी ने तीन (पेनल्टी स्ट्रोक पर) और अंकित पाल ने एक गोल किया जबकि बेल्जहयम के लिए हुजो लावुशेरे, जी हाआक्स और चार्ल्स एल ने गोल दागे। इससे पहले मैच में 45वें मिनट तक बेल्जियम ने अपनी सटीक पासिंग और गेंद पर नियंत्रण से भारत को दबाव में रखा लेकिन तीसरे क्वार्टर में कप्तान रोहित ने आखिरी मिनट में मिले पेनल्टी कार्नर पर जैसे ही बराबरी का गोल दागा, मैच की तस्वीर बदल गई। खचाखच भरे मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में मानो उत्साह का संचार हो गया। इससे दो मिनट पहले मिले पेनल्टी कार्नर पर रोहित का प्रयास

पुरुष हाकी

जीत के बाद जश्न मनाते भारतीय खिलाड़ी।

भारतीय टीम को आखिरी सीटी बजने से एक मिनट पहले कोताही बरतने का खामियाजा भुगतना पड़ा और रोजे नाथन के गोल की मदद से बेल्जियम ने मैच को शूटआउट तक खींच दिया। शूटआउट में भारत के लिए शारदानंद तिवारी ने तीन (पेनल्टी स्ट्रोक पर) और अंकित पाल ने एक गोल किया जबकि बेल्जहयम के लिए हुजो लावुशेरे, जी हाआक्स और चार्ल्स एल ने गोल दागे।

नाकाम रहने से मिली निराशा भी दूर हुई। बेल्जियम को आखिरी मिनट में लगातार तीन पेनल्टी कार्नर मिले लेकिन भारतीय डिफेंस ने इस बार कोई चूक नहीं की। चौथे क्वार्टर की शुरूआत बेल्जियम ने काफी आक्रामक की और पहले ही मिनट में पेनल्टी कार्नर बनाया लेकिन बढ़त नहीं बना सकी। भारत को जवाबी हमले में 48वें मिनट में पेनल्टी कार्नर मिला और शारदानंद तिवारी ने जैसे ही भारत को बढ़त दिलाई, पूरा स्टेडियम 'इंडिया इंडिया' के शोर से गूंज उठा। यह इत्तेफाक ही है कि शारदानंद के निर्णायक गोल की मदद से ही भारतीय जूनियर टीम भुवनेश्वर में चार साल पहले हुए टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में इसी प्रतिद्वंद्वी को एक गोल से हराकर अंतिम चार में पहुंची थी।

जूनियर महिला हाकी विश्व कप

भारत ने आयरलैंड को 4-0 से हराया

सैंटियागो, 5 दिसंबर (भाषा)।

पूर्णिमा यादव के दो गोल की बदौलत भारत ने शुक्रवार को एफआइएच जूनियर महिला विश्व कप के पूल सी के अपने अंतिम मैच में आयरलैंड को 4-0 से हराया।

पूर्णिमा (42वें, 58वें मिनट), कनिका सिवाच (12वें मिनट) और साक्षी राणा (57वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाना शुरू किया। टीम ने 12 सेकेंड के अंदर ही पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन उनका प्रयास गोल में नहीं बदला। भारत ने 10वें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कार्नर हासिल किया, लेकिन यह मौका भी बेकार चला गया। साक्षी ने इसके दो मिनट बाद सर्कल के अंदर कनिका को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने प्रतिद्वंद्वी टीम की गोलकीपर को कुशलता से चकमा देकर मैच का पहला गोल दाग दिया।

भारत ने अपने दबदबे को बरकरार रखते हुए 17वें और 23वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कार्नर हासिल किए, लेकिन आयरलैंड की गोलकीपर लुसी मैकगोल्डरिक ने दोनों मौकों पर शानदार बचाव किए। आयरलैंड की ओर से गोल पर पहला प्रयास मैच के 24वें मिनट में आया, जिसे भारतीय गोलकीपर ने बचा लिया। दूसरे क्वार्टर के अंत में भारत ने 28वें मिनट में अपना पांचवां पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन वे इस मौके को भुना नहीं सके और पहले हाफ का अंत एक गोल की बढ़त के साथ किया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा। मनीषा ने 40वें मिनट में सुखवीर कौर को एक तेज पास दिया, लेकिन उनका शाट पोस्ट के ठीक ऊपर से निकल गया। इसके दो मिनट के बाद टीम ने एक और पेनल्टी कार्नर हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन तालमेल दिखाया और साक्षी शुक्ला के दमदार पास को पूर्णिमा ने गोल पोस्ट की ओर मोड़ दिया। आयरलैंड ने चौथे क्वार्टर में आयरलैंड ने वापसी की कोशिश की और एभा कुरान ने दाएं कोने से करारा शाट खेला लेकिन उनके प्रयास को नंदिनी ने रोक दिया।

Source: - हिन्दुस्तान

■ शिखर वार्ता के बाद मोदी-पुतिन बोले- साझेदारी बढ़ाएंगे ■ दोनों देशों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत-रूस चुनौतियों के लिए तैयार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले आठ दशकों में भारत और रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह अडिग बनी हुई है। आने वाले समय में यह मित्रता वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के बाद संयुक्त बयान में यह बात कही। दोनों देशों के बीच 15 समझौते हुए।

मोदी ने कहा कि आर्थिक सहयोग को नई उंचाइयों पर ले जाना हमारी साझा प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए 2030 तक के लिए एक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है। इससे व्यापार और निवेश विविध, संतुलित और टिकाऊ बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे।

इन क्षेत्रों में साथ बढ़ेंगे: मोदी ने कहा कि कृषि और उर्वरक के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब दोनों पक्ष मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं।

तेल आपूर्ति जारी रहेगी: संयुक्त बयान में पुतिन ने कहा कि रूस भारत को निर्बाध तरीके से तेल आपूर्ति करता रहेगा। रूस तेल, गैस और कोयला के साथ जरूरत की हर चीज देगा। रूस भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके अलावा दोनों देश छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की संभावना तलाश रहे हैं।

इस बीच, रूसी समाचार एजेंसी आरआईए ने कहा कि रूस की कंपनी रोसातोम ने भारत में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर बात शुरू कर दी है।

➤ भारत में पुतिन P24

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में शुक्रवार को शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।

100 अरब डॉलर का व्यापार भारत-रूस के बीच करने पर सहमति

10 हजार करोड़ की लागत से यूरिया संयंत्र लगाएगी रूस की कंपनी

भारत को सुखोई-57 बनाने का प्रस्ताव दिया

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर रक्षा सौदे पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। हालांकि, सरकार ने ऐसी किसी भी समझौते की घोषणा नहीं की। वहीं रूस की समाचार एजेंसी तास का दावा है कि रूस ने भारत में पांचवीं पीढ़ी का सुखोई-57 स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का प्रस्ताव दिया। हाईटेक इंडस्ट्रियल उत्पादों के निर्माण पर नजर रखने वाली रूसी एजेंसी रॉस्टेक के सीईओ सेरेगी केमजोव ने ये दावा किया है।

> आर्थिक सहयोग को नई उंचाइयों पर ले जाना भारत-रूस की साझा प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए 2030 तक के लिए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

> रूस और भारत की मजबूत साझेदारी से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। रूस की कंपनियां भारत से अलग-अलग उत्पाद और सेवाओं की खरीद बढ़ाएंगी। -व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति

ये अहम समझौते हुए

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जाएगा
2. पोलर वाटर में शिपिंग के प्रशिक्षण के लिए दोनों देशों के बीच समझौता
3. भारत और रूस समुद्र में मिनरल की खोज के लिए मिलकर काम करेंगे
4. मुंबई विश्वविद्यालय और लोमोनोसोव विवि के बीच अकादमिक समझौता
5. श्रमिकों के रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया आसान होगी। दूसरा, अवैध प्रवेश रोका जाएगा
6. सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों की कस्टम एजेंसियों के बीच भी सहमति बनी है
7. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का रूसी एजेंसी के साथ उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर सहमति बनी
8. एक-दूसरे देशों में पत्र भेजने के लिए भारत और रूस की डाक एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा
9. यूरिया उत्पाद को लेकर राष्ट्रीय केमिकल और रूसी एजेंसी में समझौता। भारत में संयुक्त उपक्रम में यूरिया उत्पादन होगा
10. पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी तथा रूस के रक्षा संस्थान के साथ शोध समझौता हुआ

■ इसके अलावा प्रसार भारती और रूस के मीडिया संस्थानों के बीच पांच समझौते किए गए हैं।

खास बातें

- भारत और रूस ने अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने को पंचवर्षीय योजना पर सहमति जताई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन में जारी युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।
- भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई-पर्यटक वीजा तथा 30 दिन का समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा।
- पुतिन ने संकेत दिया कि रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाएगा। छोटे एवं 'मॉड्यूलर' परमाणु रिएक्टर के निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर विचार।
- दोनों देश यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।

कीर्तिमान : 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश का नाम वर्ल्ड बुक में दर्ज

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें यह सम्मान मिला है। नीतीश कुमार दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। शीघ्र ही उनका नाम इसमें शामिल कर उन्हें आधिकारिक रूप से इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पत्र के जरिए कहा है कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दस बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। यह पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

> यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है। – **वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स,** लंदन
> (नीतीश कुमार को भेजे पत्र में)

सूबे के 26 लाख नए घरों में पेयजल की आपूर्ति होगी

पीएचईडी ने शुरू किया काम, इस पर खर्च होंगे 7248 करोड़

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 26 लाख से अधिक नए घरों में हर घर नल का जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इनमें आठ लाख घर उन क्षेत्रों के हैं, जहां का पानी गुणवत्ता प्रभावित है। इन क्षेत्रों में पानी को स्वच्छ (शोधन) करने के बाद ही घरों में आपूर्ति की जाएगी।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि अगले एक साल के अंदर इन सभी घरों में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। विभाग के स्तर से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। 26 लाख नए घरों में पेयजल आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार से भी राशि की मांग की गई है। विभाग ने 7248 करोड़ की पुनरीक्षित राशि देने का पत्र भारत सरकार को भेजा है। वहीं, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के आठ लाख घरों में पेयजल आपूर्ति पर 2807 करोड़ खर्च होंगे। हालांकि, राज्य सरकार के कोष से पेयजल आपूर्ति का कार्य जारी है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं राज्य के 27 हजार टोलों में इन सभी घरों में नए कनेक्शन देने का काम शुरू किया है। ये सभी वैसे टोले हैं, जहां विभिन्न कारणों से इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। इनमें अधिकतर गांव की आबादी से थोड़ी दूरी पर स्थित टोले हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जहां नई बसावट है। पेयजल आपूर्ति को लेकर निविदाएं जारी कर दी गई हैं। इनमें 10 हजार टोले उन ग्राम पंचायतों में हैं, जहां पीएचईडी ने नल-जल का कनेक्शन दिया था।

75 लाख घरों तक पहुंचा कनेक्शन

ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक एक करोड़ 75 लाख से अधिक परिवार के घरों में नल-जल का कनेक्शन दिया गया है। नए टोलों में पेयजल आपूर्ति का काम पूरा होने के बाद ऐसे परिवारों की संख्या दो करोड़ से अधिक हो जाएगी। विभागीय पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना के संचालन की निगरानी प्रतिदिन विभाग के स्तर पर होती है। जहां कहीं से भी योजना में किसी त्रुटि की शिकायत मिलती है तो 24 से 48 घंटे के बीच उसे दुरुस्त कराया जाता है। शिथिलता बरतने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई की जाती है। पांच अभियंताओं को निलंबन सहित दस पर कार्रवाई की गई है।

परिवहन

परिवहन विभाग ने बिहार में नए मार्गों की पहचान कर अधिसूचित किया, पटना के धनरुआ और दानापुर से भी नए मार्ग की पहचान हुई

सुविधा : बिहार में 31 नए मार्गों पर यात्री वाहन चलाए जाएंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के कई नए मार्गों में बस-ऑटो, ई-रिक्शा समेत अन्य यात्री वाहनों का परिचालन होगा। परिवहन विभाग ने 31 नए मार्गों का चयन किया है। इन मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए विभाग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत अनुदान देगा।

113 किलोमीटर नए मार्ग की पहचान की गई : विभागीय अधिकारियों के अनुसार, शिवाजीनगर से गुदारघाट, समस्तीपुर, मुसरीघरारी, ताजपुर, पातेपुर, सुक्की, महुआ, हाजीपुर होते हुए पटना के लिए 113 किलोमीटर नए मार्ग की पहचान की गई है। पटेल चौक महनार से नवागंज बाजार, चकौसन, हाजीपुर और राजेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन, जन्दाहा से चांदसराय हाट चौक, अंबेडकर चौक, पासवान चौक, गायघाट और राजेन्द्रनगर, घोड़ासहन से ढाका, पंकपकड़ी, बेलवाघाट, पिपराढ़ी, शिवहर, परसौनी, सीतामढ़ी मार्ग की पहचान की गई है। इसी तरह चिकनी से भिठामोड़, सुरसंड, कुम्मा होते हुए सीतामढी, बासोपट्टी से भेजा, घोघरडीहा, फुलपरास, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए बरौनी जीरो माइल, मधेपुर बाजार से निर्मली होते हुए मरौना, शैलेशपुर से नवादा, मधेपुरा बाजार से झंझारपुर, कुपहा से दरभंगा, घोघरडीहा से दरभंगा, मधवापुर से सिमरिया, मधवापुर से पटना और मधवापुर से सहरसा के लिए नए मार्ग की पहचान की गई है। वहीं सिंघिया घाट से बेगूसराय, मटिहानी से अगुवानी, मटिहानी से अलौली, मटिहानी से समस्तीपुर, नारायण पिपर से बेगूसराय, दुलमपुर से जमुई, आढ़ा से जमुई, जमुई से लखीसराय, धनरुआ से इस्लामपुर, धनरुआ से जमुई रेलवे स्टेशन, दानापुर से इस्लामपुर, जमुई रेलवे स्टेशन से धनरुआ, धनरुआ से दरभंगा, धनरुआ से बिहारशरीफ, इस्लामपुर से धनरुआ नए मार्ग की पहचान की गई है।

- नए मार्गों पर बस, ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन हो सकेगा
- विभाग मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत अनुदान देगा

पूर्व से अधिसूचित तीन मार्गों में आंशिक संशोधन

पूर्व से अधिसूचित मार्गों में आंशिक संशोधन किया गया है। इनमें फुलौत से मधेपुरा, दतमई से बैरिया बस स्टैंड, नैनीजोर से बवसर शामिल है। विभाग ने इन नए मार्गों को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत अंतर्क्षेत्रीय मार्गों के रूप में अधिसूचित किया है। यानी इन मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए विभाग की ओर से लोगों को अनुदान दिया जाएगा।

बस खरीद पर पांच लाख रुपये का अनुदान

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चार सीटर से लेकर 10 सीटर तक के सवारी वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें बस से लेकर ऑटो तक शामिल है। पंचायतों में चयनित सात लाभुकों को वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख तक का अनुदान दिया जाता है। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर लाभुक को प्रति बस पांच लाख रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है।

संकट : पटना-दिल्ली का विमान किराया लंदन से भी महंगा

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानों में तीन दिनों से जारी संकट शुक्रवार को और गहरा गया। चौथे दिन बिहार में 22 सहित देशभर में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। इससे घरेलू उड़ानों का किराया आसमां पर पहुंच गया है। पटना से नई दिल्ली का किराया, नई दिल्ली से लंदन के किराये को भी पार कर गया। रविवार को पटना से नई दिल्ली (स्पाइसजेट) का विमान किराया 41380 रुपए है, जबकि उसी दिन दिल्ली से लंदन (हिथ्रो) का किराया (एयर इंडिया) 26351 रुपये है। शुक्रवार को पटना से नई दिल्ली का किराया 30 हजार रुपये के पार रहा।

इंडियो की फ्लाइट रद्द होने से एयर इंडिया, स्पाइसजेट की उड़ानों की मांग बढ़ गई हैं। कई मार्ग पर टिकटों की कीमत सामान्य दिनों की तुलना में 4 से 5 गुना तक है। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का किराया 37 हजार से 44 हजार रुपये के बीच है। सामान्य दिनों में पटना-नई दिल्ली का किराया 5 से 6 हजार के बीच होता है, जो पांच दिसंबर को 32215 रुपए, पटना से मुंबई के लिए 8-9 हजार रुपये का किराया 35-40 हजार, पटना से बेंगलुरु का किराया करीब सात हजार से बढ़कर करीब 40 हजार रुपए पहुंच गया। वहीं पटना-चेन्नई रूट पर भी टिकट की कीमतें 7-8 हजार से बढ़कर 50 हजार से ऊपर चली गई थीं। देखें P14,24

बिहार से 22 समेत देश की 1000 उड़ानें फिर रद्द रहीं

शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर फंसे यात्री।

किराया आसमान पर

6 दिसंबर	पटना-चेन्नई	₹26142
6 दिसंबर	दरभंगा-नई दिल्ली	₹37983
7 दिसंबर	दरभंगा-मुंबई	₹43256
7 दिसंबर	गया-दिल्ली	₹24400
8 दिसंबर	पटना-नई दिल्ली	₹29869
8 दिसंबर	पटना-मुंबई	₹27911
8 दिसंबर	पटना-बेंगलुरु	₹26982

डीजीसीए ने वापस लिया आदेश

डीजीसीए ने साप्ताहिक अवकाश संबंधी अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया है। कहा कि विमानों के परिचालन में आ रही बाधा और एयरलाइंस से मिले आग्रेदन पर फैसले को वापस लिया जाता है। बीते चार दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या बढ़कर 1900 के पार पहुंच गई।

> 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उम्मीद हैं कि शनिवार को रद्द उड़ानों की संख्या 1,000 से कम रहेगी। -पीटर एल्बर्स, सीईओ इंडिगो

संकट के कारण

1. **क्रू की भारी कमी:** पायलटों के साप्ताहिक आराम का समय 36 से बढ़ाकर 48 घंटे करने से स्टाफ की कमी हो गई। गया।
2. **लैंडिंग लिमिट में बदलाव:** रात में विमान उतारने की सीमा भी घटाकर दो कर दी गई है। ऐसे में उड़ान रोस्टर बनाना मुश्किल हुआ।
3. **तकनीकि में गड़बड़ी:** कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर चेक-इन और बोर्डिंगमें तकनीकी दिक्कतें आई, जिससे देरी हुई।
4. **भीड़भाड़ और खराब मौसम:** सर्दियों के मौसम में कोहरा और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़भाड़ ने स्थिति को और खराब कर दिया।

पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने की कवायद

बिहार में बनेंगे तीन नए विभाग : नीतीश

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में तीन नए विभाग बनेंगे। एक निदेशालय और एक निगम की भी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया गया है।

वर्तमान में कुल 42 विभाग हैं। इन तीन विभागों के गठन के बाद राज्य में विभागों की कुल संख्या 47 हो जाएगी। सरकार के इस निर्णय को पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य पाने की कसरत के रूप में देखा जा रहा है। इन तीन नए विभागों के सृजन से युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लक्ष्य पाने के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। पोस्ट में मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों के गठन का उद्देश्य भी स्पष्ट किया है। गौर हो कि 1989 में मानव संसाधन विकास विभाग तीन विभागों में बांटा गया था। इसमें एक उच्च शिक्षा विभाग भी था। जो बाद में खत्म हो गया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

ये नये विभाग

1. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास

मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है।

2. उच्च शिक्षा

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा मिल सके। बिहार के युवा दक्ष हों, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए कृतसंकल्पित हैं।

3. नागर विमानन

नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी।

नये निदेशालय-निगम

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय

सीएम ने कहा कि हमलोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कारपोरेशन) सृजित करने का भी निर्णय लिया है। जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। निदेशालय का गठन कर युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी।

2. बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम

बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

जमीनी हकीकत

पिकलबॉल में बिहार के बच्चों ने अबतक 50 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीते

पिकलबॉल खेल में बिहार के बच्चे देशभर में नाम रौशन कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में बिहार के बच्चे करीब 50 स्वर्ण जीत चुके हैं और इतनी ही संख्या में रजत और कांस्य पदक भी उनके हाथ आए हैं। बिहार में इस खेल को अब तक 10 राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। छह फ्रेंडशिप कप और दो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत और नेपाल के बीच हो चुकी है। यह प्रतियोगिता 2019 और 2021 में हुई थी। 2023 में दूसरी इस्टजोन पिकलबॉल प्रतियोगिता पटना में हुई थी। बिहार से तीन खिलाड़ी अविनाश कुमार, आदित्य गुप्ता और आनंद सिंह भलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाइलैंड, नेपाल में अपना परचम लहरा चुके हैं। तीनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आदित्य गुप्ता और अविनाश कुमार को ऑल इंडिया पिकलबॉल संघ पूरे सात किट, फेयर, फुटिंग और लॉजिंग उपलब्ध कराती है।

बिहार के 12 जिलों में यह खेल हो रहा: ओलंपिक संघ के अनुसार बिहार बॉल बैडमिंटन खेलने 2011 में पुणे गया था। वहीं पर पीकलबॉल को खेलते हुए देखा था। 2012 में पहली बार मगध महिला कॉलेज में मिताली मित्रा के नेतृत्व में इसकी शुरू आत की गई। आज बिहार के 12 जिलों में पिकलबॉल खेला जाता है। बिहार के सात सौ खिलाड़ी इस खेल को खेल रहे हैं और देश-दुनिया में परचम लहरा रहे हैं।

पिकलबॉल को बढ़ाने में काफी संघर्ष: पिकलबॉल संघ के सचिव रंजन कुमार गुप्ता ने बताया कि संघ को 12 साल तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। लोग इस खेल को लेकर मजाक उड़ाते थे। संघ अपने पैसे से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित किया। खेल की सारी सुविधाएं मुहैया कराई। आज कई प्रायोजक तैयार हैं। राज्य सरकार से मदद की अब तक जरूरत नहीं पड़ी है।

प्रस्तुति : नियाज आलम, राहुल कुमार सिंह
फोटो : संतोष

- बिहार के तीन खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे शानदार प्रदर्शन
- यह खेल यूएसए में प्रसिद्ध, वहां 50 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इसे खेलते हैं
- बिहार के सात सौ खिलाड़ी इस खेल को खेल रहे हैं और परचम लहरा रहे

अशियाना-दीघा रोड के रामनगरी मोड़ के पास एक निजी भवन में अभ्यास करते खिलाड़ी। • हिन्दुस्तान

बिहार ओलंपिक संघ से मान्यता के लिए आवेदन

बिहार राज्य पिकलबॉल संघ के सचिव रंजन कुमार गुप्ता ने पिकलबॉल खेल को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार ओलंपिक संघ से मान्यता के लिए आवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इसको मान्यता मिल जाएगी। इसके बाद बिहार के बच्चों को पदक लाने पर नौकरी भी मिलेगी।

रोहतास के राजीव ने जीता स्वर्ण

ऑल इंडिया पिकलबॉल संघ द्वारा चार से सात दिसंबर तक पुणे में चल रहे ओपन पीकलबॉल प्रतियोगिता में बिहार रोहतास के रहने वाले राजीव कुमार ने महाराष्ट्र के पीयूष गोयल को हराकर अंडर 19 एकल का गोल्ड जीता है। पटना के आदित्य गुप्ता एकल अंडर 19 के सेमीफाइनल में पीयूष गोयल महाराष्ट्र से 11/06 हारकर बाहर हो गए। 50 प्लस एकल में बिहार के वीरेंद्र कुमार ने रमेश साहिक तमिलनाडु को 15/01 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 35 प्लस एकल में वीरेन्द्र कुमार ने गोवा के मंदाक को 15/04 से हराकर स्वर्ण जीता।

2023 में दूसरी इस्टजोन पिकलबॉल प्रतियोगिता पटना में हुई थी

06 फ्रेंडशिप कप और दो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का हुआ है आयोजन

2008 में खेल की हुई शुरुआत

पिकलबॉल खेल की शुरूआत 2008 में मुंबई में हुई थी। सुनील वातामलकर ने इसे विदेश से लाया था। यह खेल यूएसए में प्रसिद्ध है। वहां 50 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इसे खेलते हैं। इस खेल को अभी 90 देश खेल रहे हैं। भारत चौथा राज्य है, जहां इस खेल की शुरूआत हुई। 2013 में पहली बार भारत में इसकी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी। इसमें पांच राज्य शामिल हुए थे। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पुडुचेरी शामिल हुए। आज भारत के सभी शहरों में यह खेला जाता है।

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर पटना-दिल्ली के बीच इसी माह

दिल्ली से पटना के बीच सप्ताह में छह दिन चलेगी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस

सुविधा

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिसंबर के अंत तक पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। 16 कोच वाले दो रैक के फिनिशिंग का कार्य बेंगलुरु के भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) फैक्ट्री में हो रहा है। एक रैक की फिनिशिंग पूरी हो गई है।

पहला रैक उत्तर रेलवे के लिए 12 दिसंबर को बेंगलुरु से रवाना होगी। इसके बाद दिल्ली- पटना के बीच ट्रायल रन होगा। वंदे भारत स्लीपर में 16 कोच होंगे और अलग-अलग श्रेणी के कुल 827 बर्थ होगी। थर्ड एसी के 11, सेकेंड एसी के 4 और फर्स्ट एसी का 1 कोच इसमें लगा होगा। इसके एसी 3-टीयर के 11 कोच में 611, एसी 2 टियर के 4 कोच में 188 और एसी फर्स्ट क्लास के 1 कोच में 24 बर्थ होंगे। दानापुर मंडल के अधिकारी ने भी बताया कि इस माह के अंत तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तैयारी है।

16 कोच के दो रैक बेंगलुरु के बीईएमएल फैक्ट्री में तैयार हो गए हैं

11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच में कुल 827 बर्थ होंगे

01 रैक की फिनिशिंग का काम पूरा, दूसरे का अंतिम चरण में

12 दिसंबर के पहले रैक बेंगलुरु फैक्ट्री से उत्तर रेलवे के लिए रवाना होगी

- यात्रियों की संख्या बढ़ने पर डिब्बों की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 तक की जाएगी
- ट्रेन नई दिल्ली- राजेन्द्रनगर तेजस राजधानी के समय के आसपास शाम में खुलेगी

राजेंद्र नगर से चलेगी

वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर ही वंदे भारत स्लीपर का परिचालन किया जाएगा। सप्ताह में छह दिन ट्रेनों की आवाजाही होती है। इसी के तर्ज पर वंदे भारत स्लीपर को भी सप्ताह में छह दिन ही चलाया जाएगा। पटना से यह ट्रेन नई दिल्ली- राजेन्द्रनगर तेजस राजधानी के समय के आसपास शाम में खुलेगी और सुबह दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में भी तेजस राजधानी की समय सारणी दिल्ली से होगी।

इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजे और सीसीटीवी

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में स्वचालित दरवाजे, बायो-टॉयलेट, सीसीटीवी, रीडिंग लाइट्स और आरामदायक इंटीरियर जैसी कई सुविधाएं होंगी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कवच सिस्टम और क्रैश-प्रूफ डिजाइन जैसी उन्नत सुरक्षा तकनीक लगी है। वहीं यात्रियों की संख्या बढ़ने पर डिब्बों की संख्या 16 से बढ़ाकर 24 तक की जा सकती है।

भारत-रूस दोस्ती पर फिर मजबूत मुहर

यहां स्कैन करें

सोनू सैनी | सह प्रोफेसर, रूसी अध्ययन केंद्र, जेएनयू

इस शिखर वार्ता ने उन देशों को आईना दिखाया, जो भारत-रूस दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे। यह उनको संदेश था कि आज का भारत वह नहीं है, जो किसी के दबाव में आ जाए।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (व्लादि्जमीर पुत्चिन) की भारत यात्रा इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में एक मानी जा सकती है। ऐसे वक्त में, जब रूस से संबंध आगे न बढ़ाने को लेकर भारत पर अमेरिका के साथ-साथ यूरोप के कई देशों का दबाव था, तब नई दिल्ली ने न सिर्फ गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। यह मेजबानी उन देशों को आईना दिखा रही थी, जो भारत-रूस दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे। यह उनको संदेश था कि आज का भारत वह नहीं है, जो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर अपनी दिशा तय करेगा।

शुक्रवार को हुई भारत-रूस 23वीं शिखर बैठक में कई जरूरी समझौते हुए। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सहयोग, खाद, कृषि, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज आदि क्षेत्रों में हुए समझौते तो खासा महत्वपूर्ण हैं। असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत ने जहां आलू और अनार के निर्यात को बढ़ाने की मंशा जताई, तो रूसी सेब में भी दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा, एमएसएमई और शोध-कार्यों में भी पारस्परिक रूप से आगे बढ़ने पर बात बनी है। वीजा नियमों को आसान बनाने और जन-शक्ति समझौते के अनुरूप बेहतर अवसर की तलाश में रूस जाने वाले भारतीयों की मुश्किलों को दूर करने, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस शिखर बैठक में नए समझौते तो हुए ही, पूर्व की सहमतियों पर किस तरह आगे बढ़ा जाए, उस पर भी चर्चा हुई।

राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में एक अच्छी बात यह भी रही कि वह अकेले नहीं आए। उनके साथ बड़ी संख्या में रूसी नागरिक, व्यापारी भी भारत पहुंचे, जो यहां से जुड़ना चाहते हैं और अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। यह बताता है कि रूस 'पीपुल-टु-पीपुल कॉन्टेक्ट' यानी लोगों के आपसी जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है। भारत ने भी उसे निराश नहीं किया। राजधानी दिल्ली में ही गुरुवार और शुक्रवार को तमाम तरह के आयोजन हुए, जो संकेत है कि भारत ने रूसियों का खुले दिल से स्वागत किया है।

भारत-रूस संबंध में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यह ऐसा मसला है, जिस पर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की भवें तन जाती हैं। उनकी आपत्ति मॉस्को से तेल खरीदने को लेकर है। गौरतलब है कि अमेरिका स्वयं रूस से तेल, खाद और अन्य चीजें खरीदता है, लेकिन दूसरे देशों पर आपत्ति जताता है। भारत सबसे अधिक तेल रूस से ही खरीदता है। हालांकि, पिछले दिनों इस आयात में कुछ कमी आई है, जिसे पश्चिम के देश अपने दबाव का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि आपसी व्यापार बहुत हद तक जरूरतों के हिसाब से चलता है। तेल भी अपवाद नहीं है।

अगर भारत और रूस में कोई विवाद होता, तो रूस उन भारतीय रुपयों को भारत में निवेश करने की पहल नहीं करता, जो उसे तेल के बदले मिले हैं। जो लोग नहीं जानते, उनको बता दूं कि भारत अपनी मुद्रा, यानी रुपये में ही रूस से तेल खरीदता है। इसलिए, इस रिश्ते में यदि कोई छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी भी, तो वे इस मुलाकात से दूर हो चुकी हैं।

शिखर बैठक के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन बयान दे रहे थे, तब उन्होंने रुपये और रूबल (रूस की मुद्रा) में व्यापार बढ़ाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' में सहयोग करने और नया लॉजिस्टिक मार्ग बनाने की भी बात कही। यह बताता है कि भारत की आर्थिक जरूरतों को रूस बखूबी समझता है और बंद कमरे में जब दोनों शीर्ष नेता मिले, तो उन्होंने इस पर सार्थक बातचीत की है। हालांकि, रूस की जरूरतों से भारत भी गाफिल नहीं है।

इस मुलाकात में विजन 2030 की चर्चा भी की गई। यह भारत और रूस के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग से जुड़ा दस्तावेज है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और पूंजी निवेश बढ़ाने के साथ-साथ आवागमन व उद्योग सहित तमाम संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। आज दोनों देशों के बीच करीब 65 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इसे एक साल में 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेश हो या निर्यात, सहमति यही बनी है कि साल 2030 तक आर्थिक व व्यापारिक सहयोग के बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे। इसके लिए दोनों देश मिलकर प्रयास करेंगे।

इस यात्रा में वीजा पर बनी सहमति भी महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता में यह भी तय हुआ कि जल्द ही रूस और भारत में 30 दिनों के लिए 'टूरिस्ट ग्रुप वीजा' निःशुल्क उपलब्ध होगी। व्यक्तिगत पर्यटक वीजा के नियमों को भी और सरल किया जाएगा। शिक्षा, पर्यटन, होटल जैसे तमाम क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ाने पर भी भारत और रूस सहमत हुए हैं। भारत यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन ने नया रूसी समाचार चैनल 'आरटी इंडिया' लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह चैनल 'केवल पश्चिमी' खबरों का विकल्प होगा। अभी तक भारत में अधिकतर खबरें पश्चिम से पहुंचती हैं। यह वैसा ही है, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर रूस को विलेन और पश्चिमी देशों को हीरो दिखाया जाता है।

कुल मिलाकर, यह यात्रा लोगों के आपसी जुड़ाव को नई ऊंचाई देता दिखा है। कई एमओयू पर हुए दस्तखत भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस साल रेपो दर में अबतक 1.25 प्रतिशत की कटौती की गई

नया कर्ज लेने वालों को रेपो कटौती का तुरंत लाभ मिलेगा

मौद्रिक समीक्षा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आरबीआई ने इस साल चौथी बार रेपो दर में कटौती कर कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत दी है। इसका तुरंत फायदा आवास और वाहन के लिए नया कर्ज लेने वालों को होगा। यह राहत भी सिर्फ उन्हें मिलेगी, जिनके लोन फ्लोटिंग दर वाले ईबीएलआर मानक से जुड़े होंगे।

वहीं, जिन लोगों ने पहले से इस मानक पर लोन ले रखा है, उन्हें बैंकों की ओर से घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का जोर अब इस बात पर होगा कि रेपो दर में कटौती का लाभ बैंकों से कर्ज लेने वालों को मिले। अभी बैंक दो मानकों के आधार पर ऋण देते हैं, जो फ्लोटिंग दर की श्रेणी में आते हैं। पहला है- बाहरी मानक आधारित ऋण दर (ईबीएलआर), जो सीधे तौर पर रेपो दर से जुड़ा है। आरबीआई ने अक्टूबर 2019 के बाद से सभी फ्लोटिंग दर वाले आवास ऋण को इस मानक से जोड़ा है। इसके तहत रेपो में कटौती होते ही नए ऋण पर ब्याज दर खुद हो जाती है। वहीं, जिनके लोन पहले से चल रहे हैं, उन्हें भी फायदा मिलता है लेकिन बैंकों को ब्याज कटौती की घोषणा करनी पड़ती है।

इनका इंतजार बढ़ेगा : फ्लोटिंग दर से जुड़ा दूसरा मानक 'सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर है। 7 वर्ष 2019 से पहले लिए गए अधिकांश कर्ज इससे जुड़े हैं। जिन लोगों को एमसीएलआर पर कर्ज मिला है, उन्हें इस कटौती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, इसमें बैंकों को यह तय करने का अधिकार है कि वे ग्राहकों को कितनी राहत दे सकते हैं। यानी बैंक चाहे तो फायदा सीमित कर सकते हैं। एमसीएलआर से जुड़े ऋण की ब्याज दरों में बदलाव धीमा होता है। बता दें कि वर्ष 2025 में रेपो दर में अब तक कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है।

कितनी कम होगी आवास ऋण की किस्त

(अवधि 20 साल, मौजूदा ब्याज दर 8%, संशोधित ब्याज दर 7.75%)

कर्ज राशि	वर्तमान किस्त	नई किस्त	मासिक बचत	सालाना बचत
20 लाख	16,729	16,419	310	3,720
30 लाख	25,093	24,628	465	5,580
40 लाख	33,458	32,838	620	7,440
50 लाख	41,822	41,047	775	9,300
70 लाख	58,551	57,466	1,085	13,020

(यह गणना लोन कैलकुटर पर आधारित है। इसमें बदलाव संभव है)

ग्राहकों को पूरा फायदा नहीं पहुंचा

विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई ने मौजूदा साल में पहले जो एक फीसदी की कटौती की थी, उसकी पूरी राहत आम लोगों तक नहीं पहुंची है। आरबीआई ने फरवरी से जून के बीच एक प्रतिशत (100 आधार अंक) की कटौती के परिणामस्वरूप बैंकों ने ऋण पर ब्याज दरों में औसतन 63 आधार अंक की ही कटौती की है। एमसीएलआर वाले ऋण धारकों को फायदा पाने के लिए ईबीएलआर विकल्प चुनना होगा। वहीं, फिक्स्ड ब्याज दर वाले भी इसे चुन सकते हैं।

लंबित शिकायतों का निपटारा जल्द होगा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों के समाधान के लिए जनवरी से दो महीने का अभियान शुरू करेगा। लोकपाल के पास बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ यह कदम उठाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस योजना इसका मकसद आरबीआई लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का समाधान करना है।

उपलब्धि | एक कैलेंडर में सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर बनने से सिर्फ पांच गोल दूर हैं रियाल मैड्रिड के स्ट्राइकर किलियन

दिग्गज रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब एमबापे

सैंटियागो। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, और यह बात खेलों में हमेशा से सच साबित होती रही है। अब दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक रिकॉर्ड भी टूटने की कगार पर नजर आ रहा है जो किलियन एमबापे के निशाने पर है।

पांच गोल दूर : रियाल मैड्रिड के धाकड़ स्ट्राइकर एमबापे पुर्तगाल के 40 वर्षीय फॉरवर्ड रोनाल्डो का 'सर्वाधिक क्लब गोल' का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं। फ्रांस के 26 वर्षीय युवा फॉरवर्ड ने एक कैलेंडर में सबसे ज्यादा क्लब गोल करने वाले फुटबॉलर बनने से सिर्फ पांच गोल दूर हैं जबकि इस साल अभी उन्हें पांच मैच और खेलने हैं।

असल में रोनाल्डो ने 2013 में एक कैलेंडर में सर्वाधिक 59 गोल 50 मैच में करके रिकॉर्ड अपना नाम लिखाया हुआ है। दूसरी ओर एमबापे 2025 में अब तक 55 मैचों में 55 गोल कर चुके हैं और रोनाल्डो की बराबरी से सिर्फ चार गोल दूर हैं। इन गोलों में से 25 एमबापे ने रियाल मैड्रिड की ओर से सभी प्रतियोगिताओं में 2025-26 में किए। 30 गोल उन्होंने पदार्पण सत्र (2024-25) में किए थे।

59 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2013 में एक कैलेंडर में किए थे

55 गोल एमबापे मौजूदा कैलेंडर में 55 मैच में अब तक कर चुके

अब रविवार रात को उनकी टीम को ला लिगा फुटबॉल में सेल्टा विगो की मेजबानी करनी है। एमबापे की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उम्मीद है कि वह 12 साल पुराना यह रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लेंगे।

शीर्ष स्कोरर : विश्व कप उपविजेता टीम के स्ट्राइकर एमबापे ने इस सप्ताह एथलेटिक क्लब के खिलाफ दो गोल करके टीम को जी दिलाई थी। इससे ला लिगा में 15 मै में उनके गोलों की संख्या 16 हो गई और चार में उन्होंने असिस्ट भी किया। रियाल मैड्रिड में 2024 में आने के बाद शुरुआत में एमबापे को कुछ चुनौती झेलनी पड़ी पर फिर उनकी रफ्तार कोई रोक नहीं सका। अब फुटबॉलप्रेमियों की नजर इस पर होंगी कि वह इस महीने अपने गोलों की संख्या कितना बढ़ाते हैं। रियाल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी से और ला लिगा में सेविला और अलावेस का सामना भी करना है।